RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 27 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-72 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट-2025: ग्वालियर में विकास का महा कुंभ, मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह

निवेश और उद्योगों पर फोकस, 50,000 करोड़ के प्रस्तावों की उम्मीद; टियर-2 शहरों को हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट-2025' का भव्य उद्घाटन ग्वालियर में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में यह समिट राज्य के टियर-2 और टियर-3 शहरों को औद्योगिक एवं निवेश केंद्र बनाने पर केंद्रित थी। थीम 'विकसित मध्य प्रदेश: हर क्षेत्र का अभ्युदय' के तहत आयोजन में उद्योगपति, निवेशक और नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

शाह ने उद्घाटन सत्र में कहा, मध्य प्रदेश की प्रगति देश की प्रगति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य ने इंफ्रा, निवेश और रोजगार में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह समिट राज्य को 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की संभावनाओं पर जोर दिया और केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया।

समिट में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एग्री-प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी पर सत्र आयोजित हुए। 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड बैंक और सब्सिडी नीतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, हम हर निवेशक को पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। ग्वालियर जैसे शहरों को हब बनाकर युवाओं को रोजगार देंगे।

यह आयोजन विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समिट से 1 लाख नौकरियां सृजित होंगी। ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व ने आयोजन को और भव्य बनाया। समिट राज्य की आर्थिक उड़ान का प्रतीक बनी।

भारत के निर्यात में पहली बार SUV ने कारों को पछाड़ा: 2025 में नया रिकॉर्ड

अप्रैल-नवंबर में SUV निर्यात 1.5 लाख यूनिट्स पार, कुल PV निर्यात में 52% हिस्सा; महिंद्रा, हुंडई और टाटा लीड कर रहे

भोपाल: भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पहली बार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) ने पैसेंजर कारों को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल-नवंबर 2025 में SUV का निर्यात 1.5 लाख यूनिट्स से अधिक हो गया, जो कुल पैसेंजर व्हीकल (PV) निर्यात का 52% है। SIAM के आंकड़ों के अनुसार, यह पहला मौका है जब SUV ने कारों (सेडान और हैचबैक) से आगे निकलकर निर्यात बास्केट में टॉप पोजीशन हासिल की है।

यह ट्रेंड घरेलू बाजार की पसंद को दर्शाता है, जहां SUV की हिस्सेदारी 50% पार कर चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थार और स्कॉर्पियो-N के दम पर सबसे अधिक SUV निर्यात किया, उसके बाद हुंडई (क्रेटा) और टाटा मोटर्स (नेक्सन, पंच) हैं। निर्यात मुख्य रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हो रहा है। कुल PV निर्यात 4.5 लाख यूनिट्स के करीब पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 18% अधिक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि BS6 नॉर्म्स के बाद भारतीय SUV की गुणवत्ता वैश्विक मानकों पर खरी उतर रही है। 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम से उत्पादन लागत कम हुई है। निर्यात में SUV की बढ़त से विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी और रोजगार सृजित होंगे। हालांकि, वैश्विक मंदी और टैरिफ बाधाओं से चुनौतियां हैं।

2030 तक भारत का ऑटो निर्यात 1 मिलियन यूनिट्स पार करने का लक्ष्य है, जिसमें SUV का योगदान 60% तक हो सकता है। यह बदलाव भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा।

प्राइवेट बैंक छोटे व्यवसायों के लोन में आगे: पिछले 2 सालों में PSU बैंकों की हिस्सेदारी घटी

RBI डेटा: प्राइवेट बैंकों का MSME लोन 35% बढ़ा, HDFC-ICICI लीड; PSU का शेयर 45% से 38% पर

भोपाल: भारतीय बैंकिंग सेक्टर में छोटे व्यवसायों (MSME) को लोन देने में प्राइवेट बैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं। RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में प्राइवेट बैंकों का MSME लोन पोर्टफोलियो 35% बढ़ा है, जबकि PSU बैंकों की हिस्सेदारी 45% से घटकर 38% रह गई है।

यह बदलाव डिजिटल लेंडिंग, तेज अप्रूवल और लचीली शर्तों से प्रेरित है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और Axis बैंक ने AI-बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग और को-लेंडिंग मॉडल्स से छोटे उद्यमियों को आकर्षित किया। प्राइवेट बैंकों का कुल MSME लोन अब 12 लाख करोड़ रुपये पार कर गया है। दूसरी ओर, PSU बैंक जैसे SBI और PNB सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, लेकिन प्रक्रिया की जटिलता से पिछड़ रहे हैं।

RBI गवर्नर ने कहा कि MSME सेक्टर GDP का 30% योगदान देता है और 11 करोड़ रोजगार सृजित करता है। प्राइवेट बैंकों की तेजी से NPA रेशियो कम (2.5%) रहा, जबकि PSU में 4.5% है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राइवेट बैंक फिनटेक पार्टनरशिप से ग्रामीण और महिलाओं तक पहुंच बढ़ा रहे हैं।

हालांकि, PSU बैंक CGTMSE और ECLGS जैसी स्कीमों से बड़े वॉल्यूम संभाल रहे हैं। FY26 में MSME लोन 40 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह ट्रेंड 'आत्मनिर्भर भारत' को मजबूत करेगा, लेकिन PSU को डिजिटल अपग्रेड की जरूरत है।

बजट 2026: उद्योग ने टैक्स विवादों के तेज समाधान की मांग की

फेसलेस अपील और विवाद से विश्वास स्कीम को मजबूत करने की अपील; 5 लाख करोड़ के लंबित केसों से निवेश प्रभावित

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बजट 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, और उद्योग जगत ने टैक्स विवादों के तेज और प्रभावी समाधान की बड़ी मांग रखी है। फिक्की, सीआईआई और एसोचैम जैसे संगठनों ने प्री-बजट मीटिंग्स में कहा कि 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लंबित टैक्स केस निवेशकों का भरोसा कम कर रहे हैं। उद्योग चाहता है कि फेसलेस अपील सिस्टम को और मजबूत किया जाए, विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 लाई जाए और अपील प्रक्रिया की समयसीमा तय हो।

फिक्की के प्रेसिडेंट ने कहा, टैक्स अनिश्चितता से FDI प्रभावित हो रहा है। हमें सिंगापुर जैसे मॉडल की तरह तेज रिजॉल्यूशन चाहिए, जहां 80% केस 1 साल में सुलझ जाते हैं। सीआईआई ने सुझाव दिया कि हाई वैल्यू केसों के लिए स्पेशल बेंच और AI-बेस्ड असेसमेंट हो। एसोचैम ने ट्रांसफर प्राइसिंग और GST अपील में देरी पर चिंता जताई।

वर्तमान में 4.8 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें 1.4 लाख इनकम टैक्स और 3.4 लाख GST से जुड़ी हैं। उद्योग का कहना है कि बजट में टैक्स रिफंड की समयसीमा 3 महीने और पेनल्टी में राहत दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रिजॉल्यूशन से राजस्व बढ़ेगा और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग सुधरेगी।

सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम से 2 लाख करोड़ सुलझाए हैं, लेकिन उद्योग अधिक स्थायी समाधान चाहता है। बजट 2026 में टैक्स रिफॉर्म्स पर फोकस रहने की उम्मीद है। यह मांग आत्मनिर्भर भारत और निवेश आकर्षण के लिए जरूरी है।

New Insurance Bill's Clause Triggers Fears of Board Overhaul in Sector

Fit and Proper' Reassessment for Directors Could Lead to Mass Exits; Industry Seeks Clarity Amid 100% FDI Push

New Delhi: A provision in the Insurance Laws (Amendment) Bill 2025, tabled in Parliament this winter session, has sparked widespread apprehension among insurers about potential board shake-ups. The clause mandates a fresh 'fit and proper' evaluation for all existing directors and key managerial personnel within six months of the bill's enactment, raising fears of forced exits and governance disruptions.

While the bill primarily aims to raise FDI limits to 100% and streamline regulations, this reassessment requirement intended to align with global best practices has caught the industry off-guard. Sources indicate that IRDAI will scrutinize past conduct, financial soundness, and integrity anew, potentially disqualifying long-serving directors over minor historical issues. This could lead to unnecessary churn at a time when stability is crucial for growth, said a senior executive from a leading private insurer.

The fear stems from ambiguity: Will retrospective scrutiny apply to pre-appointment records? Industry bodies like CII and FICCI have urged the government for grandfathering clauses to exempt current boards. With over 60 insurers operating, a mass overhaul could delay strategic decisions, impact stock prices, and deter foreign investors eyeing the liberalised FDI regime.

Proponents argue the provision enhances corporate governance, weeding out conflicts in promoter-driven firms. However, critics warn of overreach, especially for independent directors. The bill also proposes composite licensing and reduced solvency margins, but the board clause has overshadowed these reforms.

As debates intensify in Parliament, stakeholders await amendments. With India's insurance penetration at 4.2%, seamless leadership transitions are vital for achieving the 'Insurance for All by 2047' vision. The outcome could reshape boardrooms in a $200 billion sector.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

AI, Data Centers & Semiconductors: The New Tech Investment Cycle

India's technology landscape is entering a powerful new phase driven by three major forces: Artificial Intelligence (AI), Data Centers, and Semiconductors. Together, these technologies are creating a fresh investment cycle, transforming industries and creating opportunities for Indian companies and investors alike. As global technology demand grows, India is positioning itself as both a consumer and producer of next-generation tech solutions.

AI is no longer limited to science fiction. It is already part of daily life. Banks use AI for fraud detection, e-commerce platforms use it for personalised recommendations, and healthcare companies use it to analyse medical images. PwC estimates that AI could add around $1 trillion to India's economy by 2035, driven by growth in retail, healthcare, financial services, and manufacturing. This rising AI adoption means higher demand for computing power, data storage, and specialised semiconductor chips the core blocks of digital transformation.

One of the fastest-growing pillars of this new cycle is Data Centers. These are large facilities that store, process and manage digital information. As AI applications increase, so does the need for computing and storage capacity. The India Data Center Market was valued at about $3.1 billion in 2024 and is projected to grow at over 12% annually in the next five years. This boom is powered by cloud usage, video streaming, digital payments, and AI-based analytics.
Indian and global companies are investing heavily. Adani Enterprises has recently partnered with Edge Connex to build one of India's largest data center footprints. Reliance Jio's Data Center business is also rapidly expanding across Mumbai, Delhi, and Chennai, aiming to serve both Indian and global clients. These developments are not only strengthening India's digital backbone but also creating investment avenues through related stocks and sector funds.

Supporting data centers and AI is the world of semiconductors tiny chips that power modern electronics. Until recently, India imported nearly all of its semiconductor needs, spending about $24 billion annually. However, that is changing. In 2023, the Indian government approved a semiconductor incentive program worth ₹76,000 crore to attract investment in chip design and manufacturing. Companies like Tata Group and Vedanta-Foxconn are planning chip plants in Gujarat, signalling semiconductor incentive program worth ₹76,000 crore to attract investment in chip design and manufacturing. Companies like Tata Group and Vedanta-Foxconn are planning chip plants in Gujarat, signalling India's intent to become a semiconductor manufacturing hub.

While semiconductor manufacturing in India is still in early stages, allied sectors are already benefiting. Tata Elxsi provides design and software solutions for global semiconductor firms, and Dixon Technologies is expanding its electronicsmanufacturing services. These companies are gaining attention from investors looking to ride the next wave of tech growth.

The Indian stock market has responded positively to these themes. Technology-oriented funds and ETFs have seen increased flows. For example, Nippon India Nifty IT ETF and ICICI Prudential IT ETF have delivered strong returns over the last three years as global IT demand rose. Data center and semiconductor plays are increasingly being discussed among mid-cap and thematic funds, reflecting broader investor interest.

However, investors should be cautious. Tech cycles can be volatile, and semiconductor manufacturing requires time and substantial capital. Not all companies will benefit equally, and short-term price movements may not reflect long-term potential.

The key takeaway for Indian investors is to understand that AI, Data Centers, and Semiconductors are interconnected drivers of the next tech era. As India strengthens its position, well-chosen technology stocks, sector ETFs, and long-term investing could help investors participate in this structural growth.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

HMEL बठिंडा रिफाइनरी में 2,600 करोड़ निवेश करेगी: क्षमता और दक्षता बढ़ाने का प्लान

पंजाब की 9 MTPA रिफाइनरी में अपग्रेडेशन, पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोजन उत्पादन पर फोकस; रोजगार और आर्थिक विकास को गति

मुंबई : हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL), जो मित्तल एनर्जी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जॉइंट वेंचर है, ने पंजाब के बठिंडा रिफाइनरी में 2,600 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने, दक्षता सुधारने और नए उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित होगा। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

HMEL की बठिंडा रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। निवेश से पेट्रोकेमिकल्स इंटीग्रेशन, हाइड्रोजन उत्पादन और लो-कार्बन फ्यूल्स पर फोकस बढ़ेगा। कंपनी के सीईओ प्रभ दास ने कहा, यह निवेश हमें वैश्विक मानकों पर ले जाएगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। हम रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं।
यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें अपग्रेडेशन से उत्पादन लागत कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। पंजाब सरकार ने निवेश को स्वागत किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे 5,000 नौकरियां सृजित होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। HMEL ने हाल ही में रिफाइनरी की दक्षता 95% तक पहुंचाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत के रिफाइनिंग सेक्टर को मजबूत करेगा, जहां कुल क्षमता 250 MTPA है। HMEL का लक्ष्य FY30 तक 15 MTPA क्षमता है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देगा। कंपनी के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई।

CEO Musical Chairs: Indian Consumer Giants See Unprecedented Leadership Churn Post-Covid

From HUL to Nestlé and Britannia, Top Execs Exit Amid Margin Pressures and Growth Challenges; Signals Strategic Reset in FMCG Sector

Mumbai: India's consumer goods sector is witnessing a wave of CEO transitions at a pace unmatched since the Covid-19 disruptions of 2020-21, as companies grapple with slowing demand, margin squeezes, and shifting consumer preferences.

In recent months, Hindustan Unilever Ltd (HUL) saw Rohit Jawa take over from Sanjiv Mehta in 2023, followed by ongoing board reshuffles. Nestlé India appointed Svetlana Boldina's successor amid her departure, while Britannia Industries transitioned from Varun Berry to a new leadership pipeline. Godrej Consumer Products and Marico have also refreshed top roles, with Dabur and Colgate-Palmolive announcing changes earlier this year.

Analysts attribute this churn to post-pandemic realities: rural demand stagnation, urban premiumisation slowdown, and intense competition from D2C brands. CEOs appointed during Covid's boom are now facing a normalised, tougher market, said Abneesh Roy of Nuvama Institutional Equities. Inflation in raw materials like palm oil and cocoa, coupled with price hikes eroding volumes, has pressured profits HUL's Q2 margins dipped to 23%, Britannia's to 12%.

The transitions signal strategic pivots: greater focus on innovation, digital sales (now 15-20% of revenue), and cost optimisation. Many outgoing CEOs, tenured 10-15 years, are making way for younger leaders with e-commerce and sustainability expertise.

While disruptive short-term, experts view the shake-up positively for long-term adaptation in a $200 billion FMCG market growing at 6-8%. As India eyes premium consumption rebound, these changes could herald a more agile era for household names.

Tata Motors Accelerates EV Push: Five New Models by FY30 to Claim Segment Leadership

From Harrier EV to Avinya Series; Targets 50% PV Market Share in Electric Vehicles Amid Rs 25,000 Cr Investment

Mumbai: Tata Motors Ltd has unveiled an aggressive roadmap to launch five new electric vehicles (EVs) by FY30, reinforcing its ambition to dominate India's passenger EV segment. The announcement, made during the company's investor day, underscores Tata's commitment to capturing 50% market share in electric passenger vehicles, building on its current 65% dominance.

The lineup includes the Harrier EV (launching Q4 FY26), Sierra EV, Avinya premium series (two models by FY28-29), and a mass-market offering on the Acti.ev platform. "We are transitioning from leader to dominator in EVs," said Shailesh Chandra, MD of Tata Motors Passenger Vehicles and Tata Passenger Electric Mobility. The company plans Rs 25,000 crore investment over five years, focusing on battery localisation, charging infrastructure, and multi-powertrain flexibility.

Tata's EV portfolio Nexon, Punch, Tiago, and Tigor has sold over 2 lakh units cumulatively. With new launches, annual volumes are projected to cross 5 lakhs by FY30. The Avinya series, based on Jaguar Land Rover's EMA platform, targets premium buyers with 500+ km range and ultra-fast charging. Analysts praise the strategy amid India's EV penetration rising to 8% in FY26. Tata's vertical integration from cells to vehicles gives cost advantages, noted Motilal Oswal. The push aligns with national goals of 30% EV sales by 2030. Shares rose 2.8% to Rs 915, reflecting optimism. As competition intensifies from Hyundai and Mahindra, Tata's multi-brand approach (Tata and JLR) positions it to lead India's $50 billion EV market by decade-end.

A Behemoth is Born: Adani's Cement Empire Solidifies with Aggressive Gameplan

Rs 50,000 Cr War Chest Fuels Acquisitions and Capacity Ramp-Up; Targets 140 MTPA by 2028 to Challenge UltraTech Dominance

Mumbai: Gautam Adani's relentless push into India's cement sector has birthed a true behemoth, positioning Adani Group as the undisputed challenger to market leader UltraTech. With a string of high-profile acquisitions and a Rs 50,000 crore war chest, Adani is executing a meticulously crafted gameplan to disrupt the Rs 3 lakh crore industry.

The latest moves acquiring Orient Cement for Rs 8,100 crore and finalising Penna Cement earlier have catapulted Adani's capacity to over 100 MTPA, closing the gap with UltraTech's 150+ MTPA. Ambuja Cements, the group's flagship, now commands 20% market share in key regions like South and West India. We are building an integrated ecosystem with captive power, logistics, and raw materials to achieve cost leadership, said an Adani executive.

The strategy hinges on three pillars: inorganic growth through bolt-on buys, organic expansion via brownfield debottlenecking (adding 40 MTPA by 2028 at low capex), and sustainability targeting 100% renewable power and waste heat recovery. Adani's vertical integration, including ports and rail networks, promises Rs 500-700 per tonne cost savings, undercutting rivals.

Analysts estimate Adani could hit 140 MTPA by FY28, capturing 25-30% share amid India's 8% annual demand growth driven by infrastructure. The group's debt-fuelled aggression net debt at Rs 1.5 lakh crore raises leverage concerns, but robust cash flows from ports and power mitigate risks.

As cement prices firm up post-monsoon, Adani's scale could trigger consolidation, pressuring smaller players. With the sector eyeing $100 billion valuation by 2030, Adani's behemoth is not just challenging UltraTech it's redefining competitive dynamics, blending ambition with execution in India's building blocks race.

Bharti Enterprises, Warburg Pincus Acquire 49% in Haier India After China Nod

Strategic Deal Values Haier India at $1.5 Bn; Equal Stakes for Bharti-Warburg, Haier Retains 49%, Employees Get 2%

Mumbai: In a landmark transaction, Bharti Enterprises and private equity giant Warburg Pincus have secured a collective 49% stake in Haier Appliances India, the Indian subsidiary of Chinese consumer electronics major Haier Group. The deal, cleared by Chinese authorities after over a year of negotiations, values Haier India at approximately $1.5 billion (Rs 12,500 crore).

Under the agreement, Bharti and Warburg will hold equal stakes in the 49% block, while Haier Group retains 49%, and 2% goes to Haier India's management team. The transaction, expected to close in 3-4 months pending local approvals, marks Bharti's return to consumer durables after its Walmart partnership ended in 2013.

This collaboration accelerates Haier India's growth by combining global innovation with Bharti's networks and Warburg's scaling expertise, the companies said in a joint statement. The partnership will deepen localisation, expand manufacturing, and drive product innovation in refrigerators, ACs, TVs, and washing machines.

Haier India, the third-largest player after LG and Samsung, reported Rs 8,234 crore revenue in FY25, up 30%, with net profit surging over 200% to Rs 480 crore. Targeting Rs 11,500 crore in FY26, the infusion will fuel its 'Made in India' push.

Industry watchers see the deal as intensifying competition in the Rs 1 lakh crore durables market, challenging Korean dominance. It follows similar 'Indianisation' trends, like JSW's MG Motor stake. No Press Note 3 approval is needed, bypassing FDI hurdles for Chinese investments.

Shares of related firms reacted positively, signalling optimism for localised growth in India's booming appliances sector.

Vedanta Sesa Goa Hits 8 million Units Energy Savings Milestone with Smart Tech Upgrades

AI-Driven Systems and Efficiency Initiatives Slash Consumption; Equivalent to Powering 20,000 Homes Annually, Advancing Net-Zero Goals

Panaji: Vedanta Sesa Goa, the iron ore arm of Vedanta Limited, has achieved a remarkable 8 million units of energy savings through innovative smart systems and technological upgrades at its operations in Goa. This milestone, announced on Thursday, equates to the annual electricity needs of approximately 20,000 average Indian households and underscores the company's commitment to sustainable mining.

The savings stem from a multi-pronged approach: deployment of AI-enabled energy management systems, variable frequency drives (VFDs) in pumps and fans, LED lighting retrofits, and process optimizations across beneficiation plants and mining equipment. Our focus on digital transformation and energy efficiency has delivered tangible results, reducing both costs and carbon footprint, said Navin Jaju, CEO of Vedanta Sesa Goa Iron Ore Business.

Key initiatives include real-time monitoring via IoT sensors for predictive maintenance, cutting idle runtime by 15%, and upgrading high-energy equipment to energy-star rated alternatives. These efforts have lowered specific energy consumption by 12% year-on-year, aligning with Vedanta's group-wide target of carbon neutrality by 2050.

The achievement supports India's national goals under the Perform, Achieve, and Trade (PAT) scheme and contributes to Vedanta's ESG framework. Sesa Goa's operations, spanning mining, beneficiation, and value-added products, now operate with 30% renewable energy integration.

Analysts praise the move as a benchmark for resource-intensive industries, potentially saving Rs 50 crore annually in energy bills. As global scrutiny on mining sustainability intensifies, Vedanta Sesa Goa's innovations position it as a leader in responsible resource extraction, fostering economic value while preserving Goa's ecology.

बायोकॉन बायोलॉजिक्स को बायोसिमिलर एडालिमुमैब के वैश्विक अधिकार मिले

ह्यूमिरा का जेनेरिक वर्जन, ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में क्रांति; भारत में सस्ती दवा की उपलब्धता बढ़ेगी

बेंगलुरु: बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड ने एबवी (AbbVie) की ब्लॉकबस्टर दवा ह्यूमिरा (एडालिमुमैब) के बायोसिमिलर के वैश्विक अधिकार हासिल कर लिए हैं। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि यह सौदा वैश्विक बाजार में उसके बायोसिमिलर पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। एडालिमुमैब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस, क्रोहन डिजीज और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में उपयोग होता है।

बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एमडी और सीईओ श्वेता राजानी ने कहा, यह अधिग्रहण हमें वैश्विक स्तर पर बायोसिमिलर लीडर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराकर मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। कंपनी ने यह अधिकार एक ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत हासिल किए हैं, जिसकी डिटेल्स गोपनीय रखी गई हैं।

ह्यूमिरा वैश्विक स्तर पर 20 अरब डॉलर से अधिक की बिक्री वाली दवा है, लेकिन पेटेंट एक्सपायरी के बाद बायोसिमिलर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। बायोकॉन का बायोसिमिलर पहले से यूरोप और अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन वैश्विक अधिकार से भारत, एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में पहुंच बढ़ेगी। भारत में यह दवा 50-70% सस्ती हो सकती है, जो लाखों मरीजों को लाभ पहुंचाएगी।

बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने FY25 में बायोसिमिलर से 5,000 करोड़ राजस्व कमाया। कंपनी इंसुलिन, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में 10 से अधिक बायोसिमिलर विकसित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा भारत को बायोसिमिलर निर्यात हब बनाएगा।

शेयर बाजार में बायोकॉन के शेयर 3% चढ़े। यह कदम सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है।

गेल छत्तीसगढ़ में उर्वरक इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है

1.5 MTPA यूरिया प्लांट के लिए 10,000 करोड़ निवेश, तालचेर मॉडल पर आधारित; आत्मनिर्भर भारत और किसानों को सस्ता उर्वरक उपलब्ध कराने का लक्ष्य

जयपुर: गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) छत्तीसगढ़ में एक बड़ी उर्वरक इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता वाले यूरिया प्लांट के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह प्रोजेक्ट ओडिशा के तालचेर उर्वरक प्लांट के सफल मॉडल पर आधारित होगा, जहां कोयले से गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है।

GAIL के चेयरमैन और एमडी संदीप गुप्ता ने कहा, छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार प्रचुर हैं, जो इस प्लांट के लिए आदर्श है। हमारा लक्ष्य देश में उर्वरक उत्पादन बढ़ाना और आयात निर्भरता कम करना है। प्लांट कोल गैसिफिकेशन तकनीक से चलेगा, जो पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी है। यह प्रोजेक्ट 2029 तक चालू होने की उम्मीद है।

भारत उर्वरक का बड़ा आयातक है, जहां यूरिया आयात 30% तक है। GAIL का यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूत करेगा। प्लांट से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के किसानों को सस्ता यूरिया मिलेगा, जिससे कृषि लागत कम होगी। इससे 5,000 प्रत्यक्ष और 20,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

GAIL ने तालचेर प्लांट में सफलता हासिल की है, जो 1.3 MTPA यूरिया उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्लांट के लिए भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा और कोयला आधारित उद्योगों को नई दिशा मिलेगी।

GAIL का फोकस गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोकेमिकल्स पर भी है। FY25 में कंपनी का राजस्व 15% बढ़ा। यह प्रोजेक्ट भारत के उर्वरक उत्पादन को 50 MTPA तक ले जाने में मदद करेगा। गेल के शेयर 1.5% चढ़े। यह कदम कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है।

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेनयुस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.
- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.

EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	26042	26408	26321	26182	26095	25956	25869	25730
BANK NIFTY	59011	59865	59671	59341	59147	58817	58623	58293
SENSEX	85041	86327	86030	85535	85238	84743	84446	83951
FINNIFTY	27431	27964	27842	27637	27515	27310	27188	26983
MIDCAP	13723	14190	14092	13907	13809	13624	13526	13341
ACC	1736	1849	1822	1779	1752	1709	1682	1639
AXISBANK	1227	1254	1246	1237	1229	1220	1212	1203
ABCAPITAL	348	365	360	354	349	343	338	332
BHARTIARTL	2108	2198	2177	2143	2122	2088	2067	2033
BHEL	281	296	291	286	281	276	271	266
BIOCON	396	415	411	403	399	391	387	379
CDSL	1479	1557	1540	1510	1493	1463	1446	1416
DATAPATTERN	2681	2958	2852	2767	2661	2576	2470	2385
ESCORTS	3704	4040	3909	3807	3676	3574	3443	3341
EICHERMOTOR	7330	7507	7433	7382	7308	7257	7183	7132
FEDERAL BANK	261	279	275	268	264	257	253	246
GRINFRAPOJECT	1012	1065	1055	1033	1023	1001	991	969
HDFCBANK	993	1015	1007	1000	992	985	977	970
HCLTECH	1654	1718	1701	1678	1661	1638	1621	1598
HINDUNILVR	2288	2340	2325	2306	2291	2272	2257	2238
HAL	4414	4655	4565	4490	4400	4325	4235	4160
HYUNDAI	2319	2361	2343	2331	2313	2301	2283	2271
IOC	160	170	168	164	162	158	156	152
ICICIBANK	1350	1388	1379	1365	1356	1342	1333	1319
INFY	1657	1724	1708	1683	1667	1642	1626	1601
ITC	405	416	412	409	405	402	398	395
KOTAKBNK	2165	2207	2192	2178	2163	2149	2134	2120
LICHOUSING	540	554	548	544	538	534	528	524
LT	4051	4156	4126	4089	4059	4022	3992	3955
LUPIN	2109	2168	2151	2130	2113	2092	2075	2054
MARUTI	16573	17029	16874	16724	16569	16419	16264	16114
M&M	3627	3743	3700	3664	3621	3585	3542	3506
MGL	1136	1223	1201	1169	1147	1115	1093	1061
MAZGAONDOC	2548	2859	2744	2646	2531	2433	2318	2220
PFC	355	380	369	362	351	344	333	326
RECLTD	357	385	372	365	352	345	332	325
RELIANCE	1560	1603	1592	1576	1565	1549	1538	1522
SBIN	967	996	990	978	972	960	954	942
SUNPHARMA	1720	1824	1799	1759	1734	1694	1669	1629
SHRIRAMFINANCE	960	1059	1021	991	953	923	885	855
TITAN	3995	4142	4074	4035	3967	3928	3860	3821
TCS	3277	3368	3348	3313	3293	3258	3238	3203
TATAMOTORS	360	380	373	367	360	354	347	341
UPL	772	821	803	788	770	755	737	722
VALIENT	274	302	293	283	274	264	255	245
WIPRO	266	279	276	271	268	263	260	255

अडानी पावर का बड़ा लक्ष्य: FY32 तक 41.87 GW क्षमता, 2 लाख करोड़ का कैपेक्स

पंजाब की 9 MTPA रिफाइनरी में अपग्रेडेशन, पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोजन उत्पादन पर फोकस; रोजगार और आर्थिक विकास को गति

चंडीगढ़: हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL), जो मित्तल एनर्जी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जॉइंट वेंचर है, ने पंजाब के बठिंडा रिफाइनरी में 2,600 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने, दक्षता सुधारने और नए उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित होगा। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

HMEL की बठिंडा रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है। निवेश से पेट्रोकेमिकल्स इंटीग्रेशन, हाइड्रोजन उत्पादन और लो-कार्बन फ्यूल्स पर फोकस बढ़ेगा। कंपनी के सीईओ प्रभ दास ने कहा, यह निवेश हमें वैश्विक मानकों पर ले जाएगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। हम रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं।

यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें अपग्रेडेशन से उत्पादन लागत कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। पंजाब सरकार ने निवेश को स्वागत किया, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे 5,000 नौकरियां सृजित होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। HMEL ने हाल ही में रिफाइनरी की दक्षता 95% तक पहुंचाई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत के रिफाइनिंग सेक्टर को मजबूत करेगा, जहां कुल क्षमता 250 MTPA है। HMEL का लक्ष्य FY30 तक 15 MTPA क्षमता है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देगा। कंपनी के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in